

प्रारंभिक परीक्षा

मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS)

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के मोबाइल विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) को मंजूरी दी है।

मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) के बारे में

- **प्रकृति:** भारत में मोबाइल फोन के बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की प्रोत्साहन योजना।
- **पृष्ठभूमि:** बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLI-LSEM) के उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया गया, जिसका कार्यकाल 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गया।
- **उद्देश्य:** घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ाना, इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना, निर्यात को बढ़ावा देना और मोबाइल विनिर्माण में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
- **उत्पादन प्रोत्साहन:** भारत में निर्मित मोबाइल फोन की पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक का प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- **नवाचार प्रोत्साहन:** उत्पाद डिजाइन, अनुसंधान और विकास (R&D), और भारतीय ब्रांडों में निवेश के लिए अतिरिक्त 3% प्रोत्साहन प्रदान करता है।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और देश को वैश्विक चिप आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 को मंजूरी दी है।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 के बारे में

- **प्रकृति:** भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग, अनुसंधान और आपूर्ति श्रृंखला के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना।
- **प्रारंभ:** 2025-26 (केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित; 2026 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित)।
- **नोडल मंत्रालय:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)।
- **उद्देश्य:** घरेलू विनिर्माण, डिजाइन क्षमताओं, अनुसंधान, कुशल कार्यबल और आपूर्ति-श्रृंखला के लचीलेपन को बढ़ावा देकर एक एंड-टू-एंड (संपूर्ण) सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।

हाइड्रोजन ट्रेन

संदर्भ

प्रधानमंत्री ने हाल ही में हरियाणा में जींद-सोनीपत मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो हाइड्रोजन-आधारित रेल परिवहन में भारत के प्रवेश को चिह्नित करता है।

हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में

- **प्रकृति:** एक हाइड्रोजन ईंधन सेल-संचालित ट्रेन जो विद्युत प्रणोदन प्रणाली को संचालित करने के लिए ट्रेन के भीतर ही (ऑनबोर्ड) बिजली उत्पन्न करती है।
- **अधिकतम गति:** 75 किमी/घंटा।
- **शक्ति उत्पादन:** 2,400 kW, जो इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनसेट में से एक बनाता है।
- **हाइड्रोजन भंडारण:** उच्च दबाव में लगभग 440 किलोग्राम हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाती है।
- **आयातित प्रौद्योगिकी:** हाइड्रोजन ईंधन सेल बैलार्ड पावर सिस्टम्स (कनाडा) द्वारा आपूर्ति किए जाते हैं।
- **पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन ट्रेन:** एल्सटॉम द्वारा कोराडिया आईलेंट (Coradia iLint) 2018 में जर्मनी में लॉन्च की गई थी।
- **कार्यप्रणाली**
 - **विद्युत उत्पादन:** हाइड्रोजन ईंधन सेल और लिथियम आयरन फॉस्फेट (LiFePO₄) बैटरी का उपयोग करती है, जहां हाइड्रोजन ईंधन सेल में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके बिजली उत्पन्न करता है, जिससे केवल जलवाष्प उत्सर्जित होती है।
 - **शक्ति प्रबंधन:** ईंधन सेल निरंतर शक्ति प्रदान करता है, जबकि बैटरी त्वरण (एक्सेलरेशन) के दौरान अतिरिक्त शक्ति की आपूर्ति करती है और मांग कम होने पर अधिशेष ऊर्जा को संग्रहीत करती है; इस प्रणाली को डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (DEMU) के डीजल इंजनों को हाइड्रोजन-इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के साथ बदलकर रेट्रोफिट किया गया है।

परिवहन वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन संपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन कार्यक्रम (परिवर्तन/PARIVARTAN) योजना

संदर्भ

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तन (PARIVARTAN) योजना के दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है।

परिवर्तन (PARIVARTAN) योजना के बारे में

- **प्रकृति:** पुराने, प्रदूषणकारी वाणिज्यिक वाहनों को स्वच्छ विकल्पों के साथ बदलने के लिए एक केंद्र सरकार की योजना।
- **कार्यान्वयन मंत्रालय:** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)।

- **वित्तपोषण एजेंसी:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB)।
- **उद्देश्य:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में संचालित पुराने ट्रकों और बसों को भारत स्टेज (BS)-VI अनुपालित या इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) से बदलने की सुविधा प्रदान करना।
- **वाहन प्रोत्साहन:** मोटर वाहन कर रियायतें, पंजीकरण शुल्क छूट, और पात्र वाहन ऋणों पर 5% ब्याज अनुदान (सबवेंशन) प्रदान करता है।
- **निर्माता समर्थन:** पात्र नए वाहनों पर न्यूनतम 8% ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर (OEM) छूट को अनिवार्य करता है।
- **कवरेज:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली) और हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के एनसीआर (NCR) जिलों में लागू।

कोआला (KOALA)

संदर्भ

ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिक भविष्य में आबादी की गिरावट के खिलाफ प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक आनुवंशिक बैंकअप बनाने हेतु कोआला के अंडे और शुक्राणु को क्रायोप्रिजर्व (अत्यधिक कम तापमान पर संरक्षित) कर रहे हैं।

कोआला के बारे में

- **प्रकृति:** ऑस्ट्रेलिया का स्थानिक एक वृक्ष-वासी मार्सुपियल (एक स्तनपायी जो अपने बच्चों को एक थैली में रखता और पालता है)।
- **कुल (फैमिली):** फास्कोलाक्टिडे (Phascolarctidae), जिसकी यह एकमात्र जीवित प्रजाति है।
- **वितरण:** पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी क्वींसलैंड से लेकर दक्षिण-पश्चिमी विक्टोरिया तक पाया जाता है।
- **आवास:** नीलगिरी (यूकेलिप्टस) के जंगलों और वुडलैंड्स में निवास करता है, जहाँ यूकेलिप्टस के पेड़ भोजन और आश्रय दोनों प्रदान करते हैं।
- **व्यवहार:** मुख्य रूप से वृक्ष-वासी और एकांतप्रिय, जो कई यूकेलिप्टस पेड़ों से युक्त गृह क्षेत्र में रहते हैं।
- **जीवन शैली:** एक धीमी गति से चलने वाला शाकाहारी जो दिन में 18 घंटे तक सोता है।
- **आईयूसीएन (IUCN) रेड लिस्ट:** सुभेद्य (Vulnerable)।

अनुपस्थिति में मुकदमा (TRIAL IN ABSENTIA)

संदर्भ

जम्मू में एक विशेष एनआईए (NIA) अदालत द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के मामले में हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के बाद अनुपस्थिति में मुकदमे (ट्रायल इन एब्सेंटिया) का प्रावधान चर्चा में आया है।

अनुपस्थिति में मुकदमे के बारे में

- **परिभाषा:** आरोपी की अनुपस्थिति में आयोजित एक आपराधिक मुकदमा।

- **विधिक प्रावधान:** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 356 द्वारा शासित।
- **प्रयोज्यता:** इसे तब लागू किया जा सकता है जब कोई उद्धोषित अपराधी मुकदमे से बचने के लिए फरार हो गया हो और गिरफ्तारी की कोई तत्काल संभावना न हो।
- **उद्धोषित अपराधी:** 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास, आजीवन कारावास, या मृत्युदंड से दंडनीय मामलों में, उद्धोषणा के बावजूद उपस्थित होने में विफल रहने के बाद अदालत द्वारा फरार घोषित व्यक्ति।

स्थायी जमा सुविधा (SDF)

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त तरलता के प्रबंधन के लिए स्थायी जमा सुविधा (SDF) के माध्यम से ₹1.67 लाख करोड़ अवशोषित किए हैं।

स्थायी जमा सुविधा (SDF) के बारे में

- **प्रकृति:** बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति उपकरण।
- **प्रारंभ:** 2022 में, आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 17 में 2018 के संशोधन के बाद।
- **उद्देश्य:** अधिशेष तरलता को अवशोषित करना, मौद्रिक नीति संचरण को मजबूत करना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना।
- **संपार्श्विक (कोलैटरल) आवश्यकता:** बैंकों को बिना कोई संपार्श्विक प्रदान किए आरबीआई के पास अधिशेष धनराशि जमा करने में सक्षम बनाता है।
- **एलएएफ (LAF) कॉरिडोर की स्थिति:** फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो (FRRR) की जगह, चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) कॉरिडोर की निचली सीमा के रूप में कार्य करता है।
- **अवधि:** मुख्य रूप से ओवरनाइट जमा सुविधा के रूप में कार्य करता है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर लंबी अवधि के लिए तरलता को अवशोषित करने का लचीलापन आरबीआई के पास होता है।
- **उपलब्धता:** सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) के साथ पूरे वर्ष उपलब्ध रहता है।
- **पात्र प्रतिभागी:** पात्र वित्तीय संस्थानों को आरबीआई के पास अपनी अधिशेष धनराशि जमा करने की अनुमति देता है।

कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP)

संदर्भ

हाल ही में आई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि एक रैसमवेयर समूह ने डार्क वेब पर भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) से कथित तौर पर जुड़ा डेटा लीक किया है।

कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) के बारे में

- **स्थान:** कुडनकुलम, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु।

- **कार्यान्वयनकर्ता:** रूस के एटमस्ट्रॉयएक्सपोर्ट (Atomstroyexport) के सहयोग से न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL)।
- **उद्भव:** परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर 1988 के भारत-सोवियत समझौते के तहत स्थापित।
- **स्थिति:** भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र।

एआई स्क्वाटिंग (AI SQUATTING)

संदर्भ

साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने एआई स्क्वाटिंग के बारे में चेतावनी दी है।

एआई स्क्वाटिंग के बारे में

- एक साइबर हमला जो क्रेडेंशियल्स, डेटा चुराने या मैलवेयर वितरित करने के लिए नकली वेबसाइट, डोमेन या सॉफ्टवेयर पैकेज बनाकर एआई-जनरेटेड हैलुसिनेशन (भ्रम) का फायदा उठाता है।
- **प्रकार**
 - **फैंटम स्क्वाटिंग:** इसमें एआई-हैलुसिनेटेड डोमेन नामों को पंजीकृत करना और उनका उपयोग फ़िशिंग, क्रेडेंशियल चोरी और मैलवेयर हमलों के लिए करना शामिल है।
 - **हैलुस्क्वाटिंग:** इसमें सॉफ्टवेयर आपूर्ति श्रृंखला को लक्षित करते हुए, एआई कोडिंग सहायकों द्वारा हैलुसिनेट (भ्रमित) किए गए नामों का उपयोग करके दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर पैकेज प्रकाशित करना शामिल है।

चेंगदू जे-20 (माइटी ड्रैगन)

संदर्भ

अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर बढ़ते फोकस के बीच चीन का जे-20 (माइटी ड्रैगन) पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) की रीढ़ बनकर उभरा है।

चेंगदू जे-20 के बारे में

- **स्थिति:** चीन का पहला स्वदेशी रूप से विकसित और संचालित पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान।
- **विकासकर्ता:** पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) के लिए जे-एक्सएक्स (J-XX) कार्यक्रम के तहत चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (CAC) द्वारा विकसित।
- **स्टील्थ डिजाइन:** रडार सिग्नेचर को कम करने और गतिशीलता में सुधार करने के लिए कैनार्ड-डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन, स्टील्थ आकार, और डायवर्टरलेस सुपरसोनिक इंटेक्स (DSI) को शामिल करता है।
- **कॉम्बैट रेडियस (युद्धक दायरा):** ~2,000 किमी।
- **गति:** मैक 2+ (Mach 2+)।

मुख्य परीक्षा

महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण

संदर्भ

NFHS-6 (2023–24) के जारी होने से भारत के लैंगिक डिजिटल अंतराल (जेंडर डिजिटल डिवाइड) पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित हुआ है। यद्यपि NFHS-5 के बाद से महिलाओं के इंटरनेट उपयोग में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है, फिर भी डिजिटल पहुंच को सार्थक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण में बदलने को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

अधिक डिजिटल पहुंच महिलाओं के सशक्तिकरण में क्यों परिवर्तित नहीं हुई है?

- **स्वामित्व के बिना पहुंच:** मोबाइल फोन तक पहुंच होने का मतलब यह नहीं है कि महिलाएं इसे स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकती हैं। कई लोग साझा परिवार के फोन पर भरोसा करते हैं, जिसका उपयोग परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा नियंत्रित होता है, जिससे डिजिटल स्वायत्तता सीमित हो जाती है।
 - **उदाहरण के लिए:** NFHS-5 दर्शाता है कि कई महिलाएं मोबाइल फोन का उपयोग करती हैं, लेकिन बहुत कम महिलाओं के पास विशेष रूप से अपना मोबाइल फोन है।
- **डिजिटल क्षमता के बिना स्वामित्व:** स्मार्टफोन का मालिक होना तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक कि महिलाओं के पास सीखने, वित्त और आजीविका के लिए डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने का कौशल और आत्मविश्वास न हो।
 - **उदाहरण के लिए:** पीएमजीडिशा (PMGDISHA) ने डिजिटल साक्षरता में सुधार किया है, लेकिन कई महिलाएं अभी भी शायद ही कभी डिजिटल बैंकिंग या ई-गवर्नेंस सेवाओं का उपयोग करती हैं।
- **आर्थिक एजेंसी के बिना क्षमता:** डिजिटल कौशल सशक्तिकरण तभी पैदा करते हैं जब वे आय, उद्यमिता या रोजगार के अवसरों में तब्दील होते हैं।
 - **उदाहरण के लिए:** स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग के बावजूद ई-कॉमर्स, गिग वर्क और डिजिटल उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम बनी हुई है।
- **घरेलू स्वायत्तता के बिना आर्थिक क्षमता:** यहां तक कि डिजिटल रूप से कुशल महिलाओं में भी निर्णय लेने की शक्ति की कमी हो सकती है यदि परिवार अपने फोन के उपयोग, वित्त या ऑनलाइन गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं।
 - **उदाहरण के लिए:** LIRNEasia सर्वेक्षण परिवारों के इंटरनेट उपयोग के लिए एक प्रमुख बाधा के रूप में पारिवारिक प्रतिबंधों की पहचान करते हैं।
- **सुरक्षित डिजिटल स्थानों के बिना घरेलू स्वायत्तता:** ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग और दुर्यवहार महिलाओं को शिक्षा, कार्य या सार्वजनिक भागीदारी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से हतोत्साहित करते हैं।
 - **उदाहरण के लिए:** NCRB महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या की रिपोर्ट करता है, जिसमें साइबरस्टॉकिंग और पहचान की चोरी शामिल है।

- **समावेशी डिजिटल डिज़ाइन के बिना सुरक्षित पहुंच:** कई डिजिटल प्लेटफॉर्म साक्षर, अंग्रेजी बोलने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे वे ग्रामीण, कम साक्षरता और पहली पीढ़ी की महिला उपयोगकर्ताओं के लिए कठिन हो जाते हैं।

- **उदाहरण के लिए:** ग्रामीण महिलाओं के लिए जुगलबंदी एआई (Jugalbandi AI) जैसे वॉयस-आधारित प्लेटफॉर्म अक्सर टेक्स्ट-प्रधान सरकारी एप्लिकेशन की तुलना में उपयोग करने में आसान होते हैं।

डिजिटल एजेंसी महिलाओं को विकास के लाभार्थियों से विकास के चालकों में कैसे बदलती है?

- **स्वतंत्र निर्णय लेने को मजबूत करता है:** डिजिटल एजेंसी महिलाओं को सीधे सरकारी सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कानूनी अधिकारों और बाजार की जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाती है, जिससे सूचना और निर्णयों के लिए परिवार के सदस्यों पर निर्भरता कम हो जाती है।
 - **उदाहरण के लिए:** आयुष्मान भारत, पोषण ट्रेकर, या पीएम-किसान की जानकारी तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने वाली महिलाएं स्वास्थ्य, कल्याण और आजीविका पर समय पर निर्णय ले सकती हैं।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करता है:** डिजिटल प्लेटफॉर्म उद्यमिता, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन कार्य और डिजिटल सेवाओं के अवसर पैदा करते हैं, जिससे महिलाएं आयु उत्पन्न करने और आर्थिक विकास में योगदान करने में सक्षम होती हैं।
 - **उदाहरण के लिए:** ओएनडीसी, जीईएम और डिजिटल मार्केटप्लेस का उपयोग करने वाली महिला एसएचजी व्यवसायों का विस्तार करती हैं और व्यापक बाजारों तक पहुंचती हैं।
- **वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाता है:** डिजिटल बैंकिंग, UPI और DBT महिलाओं को स्वतंत्र रूप से धन प्राप्त करने, बचाने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे घरेलू वित्त पर नियंत्रण बढ़ता है।
 - **उदाहरण के लिए:** महिलाओं के जन धन खातों में कल्याणकारी लाभों का सीधा हस्तांतरण उनकी वित्तीय स्वतंत्रता में सुधार करता है।
- **सामाजिक पूंजी को पाटता है:** डिजिटल नेटवर्क महिलाओं को एसएचजी, निर्माता समूहों, वित्तीय संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और कानूनी सेवाओं से जोड़ता है, जिससे उनके तत्काल समुदायों से परे अवसरों का विस्तार होता है।
 - **उदाहरण के लिए:** व्हाट्सएप-आधारित एसएचजी महिलाओं को व्यावसायिक अवसरों, वित्तीय सलाह और सरकारी योजनाओं पर जानकारी साझा करने में मदद करते हैं।
- **घरेलू और सामुदायिक विकास में सुधार:** सूचना और वित्त पर अधिक नियंत्रण महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और उत्पादक निवेश पर खर्च को प्रभावित करने की अनुमति देता है, जिससे दीर्घकालिक परिवार कल्याण में सुधार होता है।
 - **उदाहरण के लिए:** महिलाओं द्वारा नियंत्रित आय बच्चों की शिक्षा और पारिवारिक स्वास्थ्य में निवेश किए जाने की अधिक संभावना है।

- **नेतृत्व और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना है:** डिजिटल एजेंसी महिलाओं को स्थानीय शासन, सामुदायिक संगठनों और सार्वजनिक प्रवचन में भाग लेने में सक्षम बनाती है, जिससे नेताओं और परिवर्तन-निर्माताओं के रूप में उनकी भूमिका मजबूत होती है।
 - **उदाहरण के लिए:** महिलाएं ग्राम सभाओं, सामुदायिक पहलों और स्थानीय उद्यमिता नेटवर्क में भाग लेने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करती हैं।

भारत महिलाओं के लिए एक समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कैसे कर सकता है?

- **किफायती उपकरण स्वामित्व को बढ़ावा देना:** लक्षित सब्सिडी, किफायती ऋण और कल्याणकारी योजनाओं के साथ एकीकरण के माध्यम से डिजिटल उपकरणों के स्वतंत्र स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से कम आय वाली और कमजोर महिलाओं के लिए।
 - **उदाहरण के लिए:** सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सुरक्षित डिजिटल पहुंच और महिलाओं के लिए किफायती स्मार्टफोन स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए **पीएमजीडिशा** जैसी पहलों को बढ़ाना।
- **लैंगिक रूप से उत्तरदायी डिजिटल साक्षरता का निर्माण:** सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सामाजिक मानदंडों को संबोधित करते हुए डिजिटल साक्षरता को डिजिटल वित्त, साइबर सुरक्षा, ई-गवर्नेंस, उद्यमिता और एआई साक्षरता को शामिल करने के लिए बुनियादी स्मार्टफोन उपयोग से परे जाना चाहिए।
 - **उदाहरण के लिए:** सिंगापुर का डिजिटल फॉर लाइफ मूवमेंट स्वयंसेवकों, गैर सरकारी संगठनों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से समुदाय-आधारित डिजिटल साक्षरता प्रदान करता है।
- **महिलाओं के डिजिटल वित्तीय समावेशन को मजबूत करना:** महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए डिजिटल वित्तीय सेवाओं को व्यक्तिगत बैंक खातों, मोबाइल स्वामित्व, वित्तीय साक्षरता और ऋण तक पहुंच से जोड़ा जाना चाहिए।
 - **उदाहरण के लिए:** केन्या के एम-पेसा ने मोबाइल भुगतान, बचत और उद्यमिता का विस्तार करके महिलाओं के वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी।
- **सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल स्पेस बनाना:** महिलाओं की ऑनलाइन आत्मविश्वास से भरी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मजबूत साइबर कानून, डिजिटल सुरक्षा शिक्षा, शिकायत निवारण तंत्र और प्लेटफॉर्म जवाबदेही आवश्यक हैं।
 - **उदाहरण के लिए:** महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा में सुधार के लिए तेजी से शिकायत निवारण, पीड़ित सहायता और लिंग-संवेदनशील साइबर पुलिसिंग के साथ **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल** को मजबूत करना।
- **समावेशी और सुलभ डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन करना:** ग्रामीण, कम साक्षरता और दिव्यांग महिलाओं के लिए पहुंच में सुधार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्थानीय भाषाओं, आवाज-सक्षम इंटरफेस, सहायक तकनीकों और उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजाइन को अपनाना चाहिए।
 - **उदाहरण के लिए:** ग्रामीण, कम साक्षरता और पहली पीढ़ी की महिला उपयोगकर्ताओं के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए **जुगलबंदी एआई** जैसे आवाज-सक्षम, बहुभाषी प्लेटफॉर्मों को बढ़ाना।

- **डिजिटल सशक्तिकरण के लिए सामुदायिक संस्थानों का लाभ उठाना:** स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), पंचायतें और नागरिक समाज संगठन सहकर्मी शिक्षा, डिजिटल प्रशिक्षण, उद्यमिता सहायता और वित्तीय समावेशन प्रदान कर सकते हैं।
 - **उदाहरण के लिए:** बांग्लादेश का ग्रामीणफोन विलेज फोन प्रोग्राम ग्रामीण महिलाओं को मोबाइल उद्यमियों के रूप में सशक्त बनाया, आय और डिजिटल समावेशन दोनों में सुधार किया।

